वे इस बात पर विवाद करते हैं कि वर्ष 1966 के बाद से ज़मीन के साथ-साथ फलों के पेड़ों की कीमतों में भी जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। हालाँकि, उनका कहना है कि किसी भी सटीकता के साथ उस वृद्धि को निर्धारित करना मुश्किल है। यह सच है फिर भी इन मामलों में चीजों की प्रकृति के अनुसार अर्जित संपत्ति का बाजार मूल्य किसी भी सटीकता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है और अनिवार्य रूप से कुछ उचित पद्धति के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इसके आलोक में हमारी यह सुविचारित राय है कि एस. हरबंस सिंह द्वारा प्रकाशित उपर्युक्त फार्मूले के आधार पर दावेदार फलों के पेड़ों की कीमत पर कम से कम 114.2 प्रतिशत की बजाय 100 की वृद्धि का हकदार है। हम प्रतिवादी के विद्वान वकील के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यह मुख्य रूप से दावेदार के लिए था कि वह उसे दिए गए मुआवजे की अपर्याप्तता को साबित करे और सरकार या अधिग्रहण करने वाले अधिकारियों का इस मामले में कोई कर्तव्य नहीं था और वे इंतजार कर सकते थे। प्रतिवादी की तरह आत्मसंतुष्टि में दावे का सबूत, और उनके आदेश पर सभी सामग्रियों द्वारा न्यायालय की सहायता किए बिना। केवल अपीलकर्ता के दावे को सबूतों के आधार पर अप्रमाणित बताकर खारिज कर देने का मतलब निश्चित रूप से यह नहीं होगा कि अधिनियम के तहत देय मुआवजे की मात्रा को स्वतंत्र रूप से और उपलब्ध सामग्री और अपनी शक्ति के सभी तरीकों से तय करने का न्यायालय का कोई कर्तव्य नहीं है।

(13) उपरोक्त के आलोक में हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और अपील के तहत निर्णयों को रद्द करते हुए, कानून और टिप्पणियों के अनुसार दावेदारों के पेड़ों के बाजार मूल्य को फिर से निर्धारित करने के लिए मामलों को संबंधित भूमि अधिग्रहण न्यायालयों को वापस भेजते हैं। ऊपर बनाया गया. यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि हमें लगता है कि कोई उचित या नियमित सुनवाई नहीं हुई है क्योंकि इस मुकदमे के पक्षकारों को पेड़ों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए ऊपर देखे गए सिद्धांतों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। यदि वे चाहें तो आगे सबूत पेश करें। अपीलकर्ताओं को इन अपीलों की पूरी लागत का भी हकदार माना जाता है।

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.-मैं सहमत हूं।

~एन.के.एस.

आर.एन.मित्तल से पहले जे.

गुरदेव राम,-याचिकाकर्ता।

बनाम

भारतीय खाद्य निगम और अन्य,-प्रतिवादी।

सिविल पुनरीक्षण संख्या 1981 का 1875.

8 फ़रवरी 1983.

मध्यस्थता अधिनियम (1940 का X)—धारा 20—सीमा अधिनियम (1963 का XXXVI)—अनुच्छेद 137—समझौता- जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल है–आवेदन किया गया। इस अनुभाग के अंतर्गत। 20.—विवादों को मध्यस्थ के पास भेजने की मांग करना–ऐसे आवेदन की सीमा–चाहे अनुच्छेद द्वारा शासित हो

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

137—अनुच्छेद 137—चाहे केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदनों पर लागू हो–अनुच्छेद 137 द्वारा निर्धारित तीन वर्ष की अवधि–ऐसी अवधि की गणना के लिए अनिवार्य शर्त।

माना गया कि सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 137 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह एक अवशिष्ट अनुच्छेद है और सभी याचिकाओं के लिए तीन साल की सीमा प्रदान करता है। परिसीमा अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि यह अनुच्छेद केवल नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत याचिकाओं पर लागू होता है, अन्य अधिनियमों के तहत याचिकाओं पर नहीं। इसलिए, किसी भी अधिनियम के तहत न्यायालय में याचिका, जिसके लिए कहीं और कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है, अनुच्छेद 137 द्वारा शासित होती है और आवेदन करने का अधिकार मिलने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर दायर की जा सकती है। नतीजतन, यह अनुच्छेद मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 20 के तहत आवेदनों पर लागू होगा।

(पैरा 7).

माना गया कि अनुच्छेद 137 में प्रावधान है कि तीन वर्ष की अवधि तब शुरू होगी जब आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होगा। मध्यस्थता के लिए आवेदन करने का अधिकार तब मिलता है जब विरोधी पक्ष आवेदक को देय कथित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है। भले ही समझौते में यह प्रावधान है कि आवेदक विपरीत पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन करेगा, इसका मतलब यह नहीं है कि सीमा की अवधि तब शुरू होगी जब विपरीत पक्ष उसे नियुक्त करने से इनकार कर देगा। धारा 20 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से विपरीत पक्ष के इनकार पर निर्भर नहीं है। एक मांग टी-.» विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना और दूसरे पक्ष द्वारा ऐसा करने से इनकार करना अदालत में आवेदन करने के अधिकार के लिए कार्रवाई के मूल तत्व नहीं हैं कि समझौता दायर किया जाए और एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाए। (पैरा 10).

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका 1908 का अधिनियम 5, श्री ए.पी. चौधरी, जिला न्यायाधीश, फ़रीदाबाद के न्यायालय के 8 मई, 1981 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए, श्री एल.एन. मित्तल, एच.सी.एस., उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, बल्लबगढ़ के 29 नवंबर, 1980 के आदेश की पुष्टि करता है। आवेदन को ख़ारिज करना और इन परिस्थितियों में पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ देना।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार।

प्रतिवादी की ओर से जी. सी. गर्ग, अधिवक्ता, हेमन्त कुमार, अधिवक्ता के साथ।

प्रलय

राजेंद्र नाथ मित्तल, जे.-

(1) यह गुरदेव राम द्वारा जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद के 8 मई, 1981 के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका है, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के तहत उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

(2) संक्षेप में, तथ्य यह है कि गुरदेव राम याचिकाकर्ता ने भारतीय खाद्य निगम के साथ एक समझौता किया (इसके बाद)

25 फरवरी, 1974 से 24 फरवरी तक एक वर्ष की अवधि के लिए, प्रतिवादी के माल की ढुलाई के लिए परिवहन की व्यवस्था करने और रेलवे स्टेशन, फ़रीदाबाद में रेलवे अधिकारियों से रेलवे रसीदों की निकासी के लिए निगम के रूप में

जाना जाता है। 1975. उनका दावा है कि रेलवे अधिकारियों ने निगम पर विलंब शुल्क लगाया और बाद में याचिकाकर्ता के बिलों से वह राशि काट ली। यह भी आरोप है कि उन्हें कुछ बिलों का भुगतान भी नहीं किया गया. रेलवे अधिकारियों ने बाद में विलंब शुल्क का 75 प्रतिशत निगम को वापस कर दिया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से रुपये की राशि का भुगतान करने का आग्रह किया। 60,721 और यदि वे राशि का भुगतान करने से इनकार करते हैं तो मामले को समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। यह कहा गया है कि उत्तरदाता इनमें से कोई भी राहत देने में विफल रहे। नतीजतन, उन्होंने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के तहत एक आवेदन दायर किया और प्रार्थना की कि उत्तरदाताओं को अदालत में मध्यस्थता समझौता दाखिल करने और उसके संदर्भ में मध्यस्थ को संदर्भ देने का निर्देश दिया जाए।

(3) आवेदन का उत्तरदाताओं द्वारा विरोध किया गया था, जिन्होंने दो प्रारंभिक आपत्तियां लीं, अर्थात्, आवेदन सीमा से वर्जित था और समझौते के खंड 12 के तहत भी, जो प्रदान करता था कि ठेकेदारों की विफलता और उनके बारे में क्षेत्रीय प्रबंधक का निर्णय निगम को होने वाले नुकसान आदि के लिए दायित्व अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी था। यह कहा गया है कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक ने याचिकाकर्ता की अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफलता और उस कारण निगम को हुए नुकसान के संबंध में अपना निर्णय पहले ही दे दिया था। इन परिस्थितियों में प्रार्थना की गई कि याचिका खारिज कर दी जाए।

(4) इसे ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिका समय से बाधित थी और याचिकाकर्ता मध्यस्थ को विवाद का संदर्भ देने का हकदार नहीं था क्योंकि मामला निगम के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा तय किया गया था। याचिकाकर्ता ने जिला न्यायाधीश, फ़रीदाबाद के समक्ष अपील की, जिन्होंने परिसीमा के बिंदु पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को उलट दिया। हालाँकि, उन्होंने दूसरे बिंदु पर उस न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की और कहा कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, मामले को मध्यस्थ के पास नहीं भेजा जा सकता है। नतीजतन, उन्होंने अपील खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने अपीलीय न्यायालय के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया है।

(5) पहला प्रश्न जिसके लिए निर्धारण की आवश्यकता है वह यह है कि क्या उपरोक्त धारा 20 के तहत याचिका परिसीमा के भीतर थी या नहीं।

यह विवादित नहीं है कि पार्टियों के बीच अनुबंध 24 फरवरी, 1975 को समाप्त हो गया और वर्तमान याचिका 19 अक्टूबर, 1979 को दायर की गई थी।

(1) विद्वान अपीलीय अदालत ने माना है कि अनुच्छेद 137

परिसीमा अधिनियम, 1963 (इसके बाद 1963 अधिनियम के रूप में संदर्भित) केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत याचिकाओं पर लागू होता है और इसलिए, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के तहत याचिकाएं इसके द्वारा शासित नहीं होती हैं।

(7) उत्तरदाताओं के लिए लर्नलर्नडकाउंसलर 1 ने उपरोक्त सभी निष्कर्षों को चुनौती दी है और आग्रह किया है कि उपरोक्त अनुच्छेद 137 एक अवशिष्ट है"/ अनुच्छेद और सभी प्रकार की याचिकाओं पर लागू होता है और केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत याचिकाओं पर लागू होता है।

मैंने उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के तर्क पर विधिवत विचार किया है और उसमें दम पाया है। अनुच्छेद 137 1963 अधिनियम की अनुसूची के तीसरे खंड के अंतर्गत आता है जो अनुप्रयोगों से संबंधित है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

आवेदन का विवरण सीमा की अवधि वह समय जिससे अवधि चलना शुरू होती है

137. कोई अन्य आवेदन जिसके लिए आवेदन करने का अधिकार अर्जित होने पर तीन वर्ष की कोई अवधि नहीं होती

सीमा अन्यत्र आईपी tfiis Divi- प्रदान की गई है

सायन.

अनुच्छेद को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह एक अवशिष्ट अनुच्छेद है और सभी याचिकाओं के लिए तीन साल की सीमा प्रदान करता है। मेरा ध्यान 1963 अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान की ओर आकर्षित नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि यह अनुच्छेद केवल नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत याचिकाओं पर लागू होता है, अन्य अधिनियमों के तहत याचिकाओं पर नहीं। इसलिए, मेरे विचार में, किसी भी अधिनियम के तहत न्यायालय में याचिका, जिसके लिए कहीं और कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है, अनुच्छेद 137 द्वारा शासित होती है और आवेदन करने का अधिकार मिलने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर दायर की जा सकती है। उक्त दृष्टिकोण से, मैं केरल राज्य विद्युत बोर्ड, त्रिवेन्द्रम बनाम मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से दृढ़ हूँ। टी. पी. कुन्हालिउम्मा (1). ए.एन. रे, सी.जे., के लिए बोलते हुए

(1) ए.जे.आर., 1977 एस.सी. म > 2 .

न्यायालय ने इस अनुच्छेद की तुलना परिसीमा अधिनियम, 1908 (इसके बाद 1908 अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अनुच्छेद 181 से करने के बाद इस प्रकार कहा:- V

"सीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 137 में विभाजन के परिवर्तन के साथ-साथ 1908 की सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 181 की तुलना में शब्दों के सह-स्थान में परिवर्तन से पता चलता है कि अनुच्छेद 137 के तहत विचार किए गए आवेदन कोड तक ही सीमित नहीं हैं। नागरिक प्रक्रिया। में

1908 परिसीमा अधिनियम, 1963 परिसीमा अधिनियम की तरह निर्दिष्ट मामलों में आवेदनों और अन्य अनुप्रयोगों के बीच कोई विभाजन नहीं था। अनुच्छेद 137 के तहत "कोई अन्य आवेदन" शब्द एडज्यूसडेम जेनेरिस के सिद्धांत पर तीसरे डिवीजन के भाग I में उल्लिखित के अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन नहीं कहा जा सकता है। अनुच्छेद 137 के तहत कोई अन्य आवेदन याचिका या किसी अधिनियम के तहत कोई आवेदन होगा। लेकिन इसे अदालत में एक आवेदन होना चाहिए क्योंकि 1963 सीमा अधिनियम की धारा 4 और 5 अदालत बंद होने पर निर्धारित अवधि की

समाप्ति और निर्धारित अवधि के विस्तार की बात करती है यदि आवेदक या अपीलकर्ता अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास पर्याप्त संपत्ति है। ऐसी अवधि के दौरान अपील न करने या आवेदन न करने का कारण।"

इसी तरह के विचार इस न्यायालय द्वारा रामजी दास और अन्य बनाम में भी लिए गए थे। दुर्गा दास (2). उसमें यह देखा गया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए कोई विशिष्ट लेख लागू नहीं था और इसलिए, 1963 अधिनियम का अनुच्छेद 137, जो एक अवशिष्ट अनुच्छेद था, लागू था।

(8) राजस्थान राज्य में राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम। एमएस। मेहता चेतन दास किशनदास (3) ने भी प्रश्न की जांच की है और माना है कि 1963 अधिनियम का अनुच्छेद 137 सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा या उसके तहत स्वीकृत आवेदनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी अधिनियम के तहत आवेदनों पर लागू होता है। एक सिविल कोर्ट. मैं आदरपूर्वक इस दृष्टिकोण से सहमत हूं।

(9) . अपीलीय न्यायालय ने यह कहते हुए कि अनुच्छेद 137 धारा 2#- के तहत याचिकाओं पर लागू नहीं होता है, वसीर चंद मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर भरोसा किया।

(2) 1979 पी.एल.आर. 673.

(3) ए.आई.आर. 1981 राजस्थान 36.

महाजन और अन्य वि. भारत संघ (4), जिसमें 1908 अधिनियम के अनुच्छेद 181 की व्याख्या सामने आई। विद्वान पीठ ने माना कि अनुच्छेद को उन लेखों के समूह में शामिल किया गया था जो "थर्ड डिवीजन-एप्लिकेशन" शीर्षक के अंतर्गत आते थे। आगे यह देखा गया कि जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, अनुच्छेद 158 से 180 के तहत किए जाने वाले सभी आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किए गए आवेदन थे और अधिकारियों का एक समूह था जो यह मानता था कि अनुच्छेद 181 में "सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत" अभिव्यक्ति है। आवश्यक रूप से अन्तर्निहित समझा जाना चाहिए। उपरोक्त टिप्पणियाँ, नई अनुसूची के प्रतिस्थापन के मद्देनजर

1963 Act, are not applicable to Article 137, though it is pari materia with Article 181 of the 1908 Act. A Division Bench of Kerala High Court in Kerala State Electricity Board v. Illippadical Parvathi Amma (5), after following Wazir Chand Mahajan's case (supra) held that Article 137 of the 1963 Act was applicable only to petitions under the Code of Civil Procedure. The said judgment was over-ruled by the Supreme Court in the Kerala State Electricity Board's case (supra). It is, thus, evident that though no reference was made in the said case by the Supreme Court to Wazir Chand Mahajan's case (supra) yet impliedly it held that the principle laid down therein was not applicable to Article

137 ibid.

(10) The Thersecond limbiofqthe question is) as toiwhen1 thetlimita of three years will start in this case. The contention of the learned counsel for the petitioner is that the limitation of three years will start from the date when the Corporation, on the application of the petitioner, refused to appoint an Arbitrator. I am not impressed with the submission. The Article provides that the period of three years will start when the right to apply accrues. The right to apply for arbitration accrued in the present case when Corporation failed to pay the amount alleged to be due to the petitioner. It is true that it was provided in clause 12 of the agreement that the petitioner would make an application for appointment of the Arbitrator but that does not mean that the period of limitation will start when the Corporation refused to appoint the same. In the aforesaid view, I find support from the observations of the Delhi High Court in Bhagwat Dayal Galgotia v. Pritam Dayal Galgotia (6). In that case too, a contention was raised by the counsel for the petitioner that the right to file a petition under section 20 of the Arbitration Act arose when the notice requiring the respondent to appoint an arbitrator

(2) A.I.R. 1967 S.C. 990.
(3) A.I.R. 1974 Kerala 202.

was given and the respondent refused to appoint. The learned Judge observed that the right to file a petition under section 20 was not dependent on the respondent's refusal to refer the dispute to arbitration. A demand to refer the dispute to arbitration and other party's refusal to do so are not ingredients of the cause of action for the right to apply to a court that the agreement be filed and an. arbitrator be appointed. I am in respectful agreement with the above-said observations. It is also relevant to mention that the learned counsel for the petitioner has fairly conceded that the present application in any case, in view of the interpretation put by me on Article 137, is barred by limitation.

In view of the fact that I have held that the petition under

धारा 20 परिसीमा द्वारा वर्जित है, अन्य प्रश्न पर जाना आवश्यक नहीं है।

(12) उपरोक्त कारणों से, मैं पुनरीक्षण याचिका को लागत सहित खारिज करता हूं। परामर्श शुल्क रु. 200.

एन.के.एस.

(6) ए.आई.आर. 11980 दिल्ली225

10937 एचसी-गवर्नमेंट पाई निबंध, यूटी च्ड

स्थानीय : भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तांकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उददेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अर्शवीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा